[2015] 1 एस. सी. आर. 328

विनोद कुमार

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1401/2008)

08 जनवरी, 2015

[न्यायाधिपति दीपक मिश्रा और न्यायाधिपति एन. वी. रमना]

दंड संहिता, 1860 – धाराये 363/109/364 ए - फिरौती के लिए अपहरण - आरोप है कि पीडब्लू-2 के घर में काम करने वाले अपीलकर्ता-घरेलू नौकर ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर पीडब्लू-2 के नाबालिग बेटे का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया - मुकदमा अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त के विरुद्ध। 363/109/364 ए – विचारण न्यायालय द्वारा बरी करना, हालांकि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया - उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप - माना गया: नहीं बुलाया गया - सह-अभियुक्तों को बरी करने से अपीलकर्ता के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा -आरोपी - अपहृत लड़के को अपीलकर्ता के पास से बरामद कर लिया गया - पीडब्लू-3 ने स्पष्ट रूप से बताया कि उसने बच्चे को अपीलकर्ता के साथ देखा था - भले ही पीडब्लू-3 के साक्ष्य में कुछ विसंगतियां थीं, उसके संस्करण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था - ये पहलू महत्व रखते हैं अभियुक्त के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त - साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा बताई गई विसंगतियाँ मामूली प्रकृति की थीं।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. सबूतों का विश्लेषण करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि 'जेजी' को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था, उन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ सबूतों की जांच करना शुरू कर दिया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक पहलू यह है कि आरोपी को दोषी नहीं पाया जा सकता क्योंकि 'जेजी' के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित मामले में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। अभियोजन पक्ष का मामला था कि 'जेजी' ने अपराध में सहयोग किया था क्योंकि उसने आरोपी को बच्चे के अपहरण के लिए उकसाया था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसके बरी होने से अभियुक्त के मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने ट्रायल जज के उक्त तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया। [पैरा 18] [342-डी-जी]

1.2. विचारण न्यायाधीश ने 'एस' द्वारा 'एम' को पत्र सौंपने के संबंध में विसंगतियां पाईं; गवाहों द्वारा बताए गए विभिन्न पहलुओं और गिरफ्तारी के समय आरोपी की पहचान से संबंधित स्थान और समय से संबंधित विसंगतियां। जो विसंगतियां नोट की गई हैं वे बिल्कुल मामूली हैं। उच्च न्यायालय ने सही कहा कि छोटी-मोटी विसंगतियों जैसे कि कौन किससे मिला, किस समय मिला और किसे छोड़ा गया और किसके स्थान पर और किस समय आदि पर अनावश्यक जोर दिया गया है। कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मामले के मूल को न छूने वाले या मामले की जड़ तक न जाने वाले छोटे-छोटे मामलों पर छोटी-मोटी विसंगतियों के परिणामस्वरूप पूरे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमति है कि विचारण न्यायाधीश ने वास्तव में उन विसंगतियों पर अनुचित जोर दिया है जो प्रकृति में मामूली हैं। विचारण न्यायाधीश के अतितकनीकी दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय ने सही ढंग से स्वीकार नहीं किया है। [पैरा 19,20] [342-जी-एच; 343-ए-बी, ई; 344-ए]

1.3. जहां तक अभियुक्त द्वारा दी गई दलील के आधार पर पत्रों की अनदेखी का संबंध है, ट्रायल जज ने थोड़े अजीब तरीके से इस पहलू पर विचार किया। यह मानते हुए भी कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में यह दलील दी गई थी कि उसने पुलिस के दबाव में आकर पत्र लिखे थे, तो भी उक्त रुख दो आधारों पर स्वीकार करने योग्य नहीं है, कि उसने पत्र लिखते समय यह आरोप नहीं लगाया था। उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीडब्लू-11 द्वारा दिखाया गया था, और वास्तव में उन्होंने पत्रों की सत्यता को स्वीकार किया था और गवाहों की जिरह में पीडब्लू-12 से बेतुके सवालों को छोड़कर, इस संबंध में कुछ भी नहीं रखा गया है। पत्रों को. यहां यह कहना उचित है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पीडब्लू-11 के रूप में पूछताछ की गई और उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि पत्र उनके सामने पेश किए गए थे और आरोपी -8 अपीलकर्ता ने पत्रों की पहचान की थी और अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे। जिरह में कुछ भी पता नहीं चल सका है। इसी तरह, वास्तव में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है कि पत्र पुलिस के दबाव में लिखे गए थे। मौजूदा मामले में, गवाह की जिरह के अभाव में, पीडब्लू-12 को एक स्पष्ट सुझाव को छोड़कर, अपीलकर्ता पत्रों का लेखक था और इसे किसी दबाव में नहीं लिखा गया था। [पैरा 21, 23, 24] [344-बी-सी; 346-ई-एफ; 348-डी-ई]

1.4. गौरतलब है कि अपहृत बालक को रेलवे स्टेशन पर बरामद किया गया था. आरोपी ने यह नहीं बताया कि बच्चे को दिल्ली कैसे लाया जा सकता है। पीडब्लू-3 ने स्पष्ट रूप से बताया कि उसने बच्चे को आरोपी के साथ देखा था। ट्रायल जज ने पीडब्लू-3 के साक्ष्य में कुछ विसंगतियां नोट कीं, लेकिन बिना किसी उचित कारण के। विचारण न्यायाधीश ने वास्तव में महत्वहीन और अनावश्यक विवरणों की अनदेखी की। पीडब्लू-3 की ओर से आरोपी से सवाल पूछना काफी स्वाभाविक है क्योंकि वह एक घरेलू नौकर को बच्चे को ले जाते हुए देखने के लिए थोड़ा चिंतित था। यह मानव

स्वभाव में अंतर्निहित है और इसलिए, पीडब्लू-3 के संस्करण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये पहलू आरोपी पर काफी भारी पड़ते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पलटने का निर्णय बिल्कुल बचाव योग्य है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 25 और 26] [348-एफ-एच; 349-ए]

जदुनाथ सिंह बनाम यूपी राज्य (1971) 3 एससीसी 577; दामोदरप्रसाद चंद्रिकाप्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य 1972 (2) एससीआर 622: (1972) 1 एससीसी 107; शिवाजी साहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 1974 (1) एससीआर" 489: (1973) 2 एससीसी 793; कर्नाटक राज्य बनाम के. गोपालकृष्ण (2005) 9 एससीसी 291; अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 (4) पूरक .विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य 331 एससीआर 449: (2004) 13 एससीसी 257; गिरजा प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। 2007 (9) एससीआर 483: (2007) 7 एससीसी 625; एस. गणेशन बनाम रामा रघुरामन 2011 (1) एससीआर 27: (2011) 2 एससीसी 83;चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य 2007 (2) एससीआर 630 :(2007) 4 एससीसी 415; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथोनी (1985) 1एससीसी 505; रम्मी बनाम म.प्र. राज्य 1999 (3) सप्ल. एससीआर 1: (1999) 8 एससीसी 649; अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य (1988) सपोर्ट एससीसी 241; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नाहर सिंह 1998 (1) एससीआर 948: (1998) 3 सेकंड 561 - संदर्भित।

वाद कानून संदर्भित

(1971)3 एस सी सी 577	संदर्भित	पैरा 13
1972(2)एस सी आर 622	संदर्भित	पैरा 14
1974(1)एस सी आर 489	संदर्भित	पैरा 14
(2005)9 एस सी सी 291	संदर्भित	पैरा 14

2004(4)पूरक एस सी आर 449	संदर्भित	पैरा 14
2007(9)एस सी आर 483	संदर्भित	पैरा 14
2011(1)एस सी आर 27	संदर्भित	पैरा 14
2007(2)एस सी आर 630	संदर्भित	पैरा 15
(1985)1 एस सी सी 505	संदर्भित	पैरा 19
1999 (3)पूरक एस सी आर 1	संदर्भित	पैरा 19
(1988)पूरक एस सी सी 241	संदर्भित	पैरा 19
1998(1)एस सी आर 948	संदर्भित	पैरा 24

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1401/2008

आपराधिक अपील संख्या 245-डीबीए/98 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07-07-2008 से।

अपीलार्थी की ओर से राजीव सिंह, विजयलक्ष्मी।

प्रतिवादी की ओर से विकास शर्मा, कमल मोहन गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधिपति दीपक मिश्रा

1. वर्तमान अपील 1998 की आपराधिक अपील संख्या 245-खंड पीठ में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज सजा के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत डिवीजन बेंच ने फैसले को उलट दिया है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय), जींद द्वारा प्रस्तुत, जिसमें विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त, जोगिंदर को भारतीय दंड संहिता, 1860

की धारा 363/109/364-ए के तहत उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया था। (संक्षेप में 'आईपीसी')।

2. अपील के निपटान के लिए जो तथ्य बताए जाने आवश्यक हैं, वे यह हैं कि जयवीर सिंह, सूचक, पीडब्लू-1, अपने दो भाइयों के साथ ग्राम लक्कस में संयुक्त रूप से रह रहा था। उनके छोटे भाई जगबीर सिंह रेलवे पुलिस में कर्मचारी थे। आरोपी-अपीलकर्ता, विनोद कुमार, बिजवासन का निवासी, मई 1996 के महीने में पीडब्लू -1 के गाँव आया था और जगबीर सिंह के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम किया था। जगबीर सिंह के चार बच्चे थे और उन्होंने दो नौकर रखे थे जिनमें से एक वर्तमान अपीलकर्ता था। जगबीर सिंह के घर में चार महीने तक काम करने के बाद, अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, विनोद कुमार ने जगबीर सिंह और श्रीमती के 3 1/2 वर्षीय बेटे आनंद का अपहरण कर लिया। संतोष, पीडब्लू-2, 24.09.1996 को। पीडब्लू-3 के हरपाल ने उसे आनंद के साथ देखा था, जिसने विनोद कुमार से पूछा था कि वह बच्चे को लेकर कहां जा रहा है, जिस पर जवाब मिला कि उसे आनंद के लिए जूते और अपने लिए दवाइयां जींद से खरीदनी थीं। माँ, पीडब्लू-2, ने बच्चे की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला, लेकिन एक पत्र, एक्ज़िबिट पी3 मिला, जो उसके ससुर मनफुल को संबोधित था। उक्त पत्र विनोद ने लिखा था कि वह आनंद को अपने साथ ले जा रहा है और एक लाख रुपये की फिरौती देने पर ही उसे छोड़ेगा। उसने तुरंत अपने ससुर के ध्यान में पत्र लाया, जिन्होंने जयवीर को पुलिस स्टेशन भेजा और जयवीर ने बदले में एक प्राथमिकी दर्ज की। आपराधिक कानून लागू होने के बाद, जांच अधिकारी गांव लक्कस गए, जहां जगबीर सिंह का घर स्थित है, साइट प्लान तैयार किया, मेमोरेंडम एक्ज़िबिट पीबी के माध्यम से विनेद द्वारा लिखे गए दो अन्य पत्र, प्रदर्शन पी 1 और पी 2 को जब्त कर लिया। जिसे संतोष, पीडब्लू-2, और उसके ससुर मनफूल द्वारा प्रमाणित किया गया था। इसके बाद जांच टीम विनाेद कुमार की तलाश में बिजवासन गांव गई, लेकिन वह गांव में नहीं मिला। इसके बाद जयवीर ने जांच अधिकारी को बताया कि

विनाेद कुमार गांव बेरी में किसी परीक्षा में बैठा था। स्कूल के शिक्षकों से उन्हें पता चला कि विनाेद कुमार उक्त स्कूल का छात्र था, लेकिन पिछले सात माह से स्कूल नहीं आया था. उन्हें यह भी पता चला कि विनाेद कुमार के पिता का नाम ओमप्रकाश है, जाे गांव ढांसा का रहने वाला है. जैसे-जैसे अभियोजन की कहानी आगे बढ़ती गई, जांच टीम धनसा गांव की ओर बढ़ी और ओम प्रकाश द्वारा विनाेद कुमार की तस्वीर दिखाई गई और उक्त तस्वीर अपीलकर्ता की थी, जिसे जगबीर ने नौकर के रूप में नियुक्त किया था। अगले दिन, एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन, जीन्द, पीडब्लू-13 को जांच टीम के अन्य सदस्यों के साथ पता चला कि आनंद को विनाेद कुमार की हिरासत से बरामद किया गया था। आरोपी-अपीलकर्ता को 26.9.1996 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। अंततः, उन्हें पत्रों के साथ विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीडब्लू-11, जींद के समक्ष पेश किया गया और विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष, उन्होंने स्वीकार किया कि पत्र उनके द्वारा लिखे गए थे और, तदनुसार, उनका बयान विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, दोनों आरोपी व्यक्तियों, विनाेद कुमार और जोगिंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 364-ए के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र पेश किया, जिन्होंने बदले में, मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

3. दोनों आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 13 गवाहों से पूछताछ की। मुख्य गवाह जयवीर सिंह, पीडब्लू-1 हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज की थी; श्रीमती संतोष, पीडब्लू-2, आनंद की मां; हरपाल, पीडब्लू-3, जिन्होंने आरोपी को आनंद को तिपहिया वाहन में जींद की ओर ले जाते देखा था; महिपाल, हेड कांस्टेबल,

जीआरपी, पीडब्लू-5, जिसने आनंद को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विनोद की हिरासत से बरामद किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था; श्री धर्म पाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जींद, पीडब्लू-11, जिनके समक्ष अभियुक्त ने बयान दिया था कि वह पत्र लिखे थे; दत्ता राम, एएसआई, जांच अधिकारी, पीडब्लू-12। अन्य गवाह, बलजीत, शक्ति, रामपाल रायसिंह, देवानंद, बलवंत सिंह और एस.एच.ओ., पी.एस. जिंद पीडब्ल्यू- क्रमशः 4,6,7,8,9, 10 और 13 जो मूल रूप से औपचारिक गवाह हैं।

5. आरोपी-अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में दलील दी कि उसे अपराध में झूठा फंसाया गया था क्योंकि उसने जगबीर सिंह के घर में काम करने की अनिच्छा व्यक्त की थी और अपने वेतन की मांग की थी। उनका आगे का रुख यह था कि नियोक्ता ने भुगतान करने से इनकार कर दिया था और उन्हें झूठे मामले में शामिल किया था। पत्रों के बारे में बताते हुए उनकी दलील थी कि उनके हस्ताक्षर जबरन लिए गए थे और पुलिस के दबाव में उनसे पत्र लिखवाए गए थे. हालाँकि, बचाव पक्ष ने कोई सबूत पेश नहीं करने का फैसला किया

6. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी जोगिंदर के खिलाफ कोई मामला स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि उसका नाम एफआईआर में उल्लेखित नहीं था और किसी भी गवाह का उल्लेख नहीं था। उसे फंसाया था और आरोपी विनोद कुमार के प्रकटीकरण बयान से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत जोगिंदर के खिलाफ माना जा सके, और तदनुसार उसे बरी कर दिया गया। जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का सवाल है, विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने पाया कि हालांकि अभियुक्त विनोद कुमार ने कुछ समय के लिए पीडब्लू-1 के भाई के ससुराल के घर में काम किया था और उनकी सिफारिश पर वह काम करने आया था। पीडब्लू-2 के

पति का घर और कथित तौर पर वहां चार महीने तक काम किया, फिर भी किसी ने उसके/माता-पिता का पता लगाने की जहमत नहीं उठाई; पीडब्लू-4 और 5 के साक्ष्य से, एक निश्चित निष्कर्ष पर आना मुश्किल था कि आनंद को आरोपी विनोद कुमार की हिरासत से बरामद किया गया था; आनंद के अपहरण के समय और मामले के पंजीकरण के संबंध में, पीडब्लू 1,3 और 12 के साक्ष्य असंगत हैं और इसलिए, उनकी गवाही को विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती; आरोपी के पिता के नाम में विसंगति थी, क्योंकि कुछ स्थानों पर उसे सूरजभान का पुत्र बताया गया था जबकि वह वास्तव में ओम प्रकाश का पुत्र है; कि पत्र, प्रदर्शन पी1 से पी3, जो अभियोजन के मामले की नींव थे, पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यदि उक्त पत्रों में कोई सच्चाई होती, तो पुलिस उस समय तक संबंधित स्थान पर इंतजार कर सकती थी जो कि था फिरौती वसूलने के उद्देश्य से उल्लेख किया गया है और इसके अलावा जांच एजेंसी ने पत्रों में दिए गए स्थान पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया है; कि 24.9.1996 यानी एफआईआर दर्ज करने की तारीख से पहले पत्रों के अस्तित्व के संबंध में संदेह था; आरोपियों की दलील है कि जो पत्र मिले थे दबाव में पुलिस द्वारा उससे लिखे गए पत्रों ने अभियोजन पक्ष के संस्करण में सेंध लगा दी और इसके अलावा जब सबूतों की पृष्ठभूमि में इसकी सराहना की जाती है तो पत्रों को विश्वसनीयता देना मुश्किल होता है; आनंद को दिल्ली से लखनऊ वापस लाने के संबंध में पीडब्लू 1, 2 और 12 के बयानों में भौतिक विसंगति थी; कि पीडब्लू 1 और 4 ने मामले के वास्तविक तथ्यों की परवाह किए बिना अपने तरीके से तथ्यों के बारे में गवाही दी थी और वे इच्छुक गवाह हैं; और पीडब्लू 4 और 5 के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में अलग-अलग विवरण दिए थे जिससे आनंद को बरामद किया गया था। इस दृष्टिकोण से, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दोनों आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया।

7. अभियोजन पक्ष ने दोषमुक्ति के उक्त फैसले से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति मांगी। जोगिंदर के खिलाफ छुट्टी के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और, छुट्टी देने की प्रार्थना विनोद कुमार तक ही सीमित थी।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि आनंद को थ्रीव्हीलर में जींद की ओर जाते समय आरोपी विनोद कुमार के साथ देखा गया था; कि पुलिस द्वारा बरामद किए गए और अभियुक्तों द्वारा लिखे गए पत्रों एक्ज़िबिट पी1 से पी3 को खारिज करने का कोई वारंट या औचित्य नहीं था; यह दलील दी गई कि पुलिस ने दबाव में उससे पत्र लिखवाए थे, ऐसा कहीं भी किसी गवाह को नहीं बताया गया; विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के पिता के नाम पर अनुचित जोर दिया था, जबकि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए सामग्री है कि उसने अपने पिता का नाम बिजवासन निवासी सूरज भान बताया था; कि विचारण न्यायालय द्वारा जिन विसंगतियों को उजागर किया गया था, वे प्रकृति में छोटी थीं और गवाहों की अन्यथा अपरिवर्तनीय गवाही को खारिज करने पर विचार नहीं किया जा सकता था; और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना मूल रूप से भ्रामक थी और इसलिए, व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को दूर से भी प्रशंसनीय नहीं माना जा सकता था।

9. उच्च न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को आरोपी-प्रतिवादी ने ट्रायल जज द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर खारिज कर दिया।

10. जैसा कि हमने देखा है, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की विस्तार से जांच की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि विनोद कुमार को हरपाल सिंह, पीडब्लू-3 ने देखा था, जिन्होंने उनसे पूछताछ की थी कि वह पोते के साथ कहां जा रहे थे। मनफुल का कहना है कि 24.9.1996 को शिकायत के साथ एक पत्र पुलिस के सामने पेश किया गया था, जिसने औपचारिक एफआईआर दर्ज करने को जन्म दिया

कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विनोद कुमार की हिरासत से लड़के आनंद की बरामदगी पूरी तरह से साबित हो गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा कि जोगिंदर को बरी करना विनोद कुमार को बरी करने की रिकॉर्डिंग के लिए विचार करने योग्य कारक नहीं हो सकता; ट्रायल कोर्ट ने आरोपी विनोद कुमार के पिता के नाम पर अनावश्यक जोर दिया था, क्योंकि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि उन्होंने खुद गवाहों के सामने कहा था कि वह सूरज भान का बेटा है; प्रदर्शन पी1 से पी3 में लिखी बातों पर इस आधार पर अविश्वास करने का रिकॉर्ड कि वे जोगिंदर के कहने पर या पुलिस के दबाव में लिखी गई हैं। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने राय दी है कि विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण बिल्कुल अस्थिर है और वास्तव में, तथ्यों की पूरी तरह से गलत समझ और कुछ अनुमानों पर आधारित है और तदनुसार बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया है।

11. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री राजीव सिंह और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री विकास शर्मा को सुना है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि बरी करने के फैसले को पलटते समय और दोषसिद्धि दर्ज करते समय, पर्याप्त कारण बताना और हर पहलू को पूरा करना उच्च न्यायालय का दायित्व है, लेकिन आक्षेपित फैसले में पलटने के लिए कोई चर्चा नहीं है। वही और, इसलिए, यह इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने गुप्त तरीके से गलत तरीके से यह माना है कि विसंगतियां प्रकृति में छोटी हैं, हालांकि उन्होंने वास्तव में अभियोजन संस्करण पर संदेह जताया है, जिसे विद्वान ट्रायल जज ने उचित रूप से सराहा है। विद्वान वकील का तर्क होगा कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह नोट कर लिया है कि आरोपी ने एक शब्द भी नहीं कहा है कि जोगिंदर ने उससे पत्र लिखवाए थे या पुलिस के दबाव में पत्र लिखवाए थे, क्योंकि दर्ज किए गए बयान में एक निश्चित रुख है। सीआरपीसी की धारा 313 में कहा गया है कि पत्र पुलिस के दबाव में लिखे गए थे। आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह एक ऐसा

मामला है जहां अपीलकर्ता को समय और स्थान से संबंधित विसंगतियों और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में ली गई दलील और अपहृत लड़के की बरामदगी के संबंध में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

12. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विकास शर्मा यह तर्क देंगे कि विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा बताई गई विसंगतियां बिल्कुल मामूली प्रकृति की हैं और किसी भी परिस्थिति में, गवाहों की गवाही को बदनाम नहीं कर सकती हैं। उनके द्वारा यह कहा गया है कि आरोपी की यह दलील कि पत्र पुलिस के दबाव में लिखे गए थे, खारिज करने योग्य है क्योंकि बचाव पक्ष ने वास्तव में पत्र के संबंध में गवाहों से कोई सवाल नहीं पूछा था, सिवाय पीडब्लू 12 को दिए गए एक गंजे सुझाव के। वकील का तर्क होगा कि यद्यपि उक्त पहलू को उच्च न्यायालय द्वारा थोड़ी गलती से समझा गया है, लेकिन इससे दोषसिद्धि का निर्णय गलत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि आरोपी अपीलकर्ता को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था और तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था और उसकी हिरासत से अपहृत लड़के को बरामद किया गया था। विद्वान वकील आगे आग्रह करेंगे कि उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के फैसले में सही हस्तक्षेप किया है और इसलिए, अपीलीय अदालत द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है।

13. इससे पहले कि हम तथ्यात्मक स्कोर पर ध्यान दें कि क्या अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्धि के लिए मामले को साबित कर दिया है, हम बरी होने के खिलाफ अपील पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित सिद्धांतों को दोबारा दोहराना उचित समझते हैं। इस संदर्भ में, जदुनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी१ से एक अंश को पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक होगा:

"इस न्यायालय ने लगातार यह विचार किया है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय के पास बड़े पैमाने पर सभी सबूतों की समीक्षा करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की पूरी शक्ति है कि उन सबूतों के आधार पर बरी करने के आदेश को उलट दिया जाना चाहिए। अपीलीय अदालत की यह शक्ति शिया स्वरूप बनाम किंग एम्पररर२ और नूरमोहम्मद बनाम एम्परर ३ में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील तैयार की गई थी। इन दो निर्णयों को इस न्यायालय के निर्णयों में लगातार वास्तविक दायरे को निर्धारित करने के रूप में संदर्भित किया गया है। आपराधिक अपील सुनने में अपीलीय अदालत की शक्ति (सूरजपाल सिंह बनाम राज्य ४ और सांवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य ५ देखें)।"

14. दामोदरप्रसाद चंद्रिकाप्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य६, शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य७, कर्नाटक राज्य बनाम के गोपालकृष्ण८, अनिल कुमार बनाम यूपी राज्य ९, गिरजा प्रसाद बनाम एमपी राज्य१० और एस गणेशन बनाम राम रघुरामन११ में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

15. इस संबंध में, हम स्वयं को चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य१२ में उल्लिखित सिद्धांतों को याद दिला सकते हैं:

"42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे विचार में, दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय अदालत की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं:

(1) एक अपीलीय अदालत के पास उन सबूतों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है।

(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और अपीलीय अदालत तथ्य और कानून दोनों के सवालों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों पर विचार कर सकती है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ', आदि का उद्देश्य अपीलीय अदालत की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। बरी किये जाने के विरुद्ध अपील में। इस तरह की पदावली 'भाषा के पनपने' की प्रकृति में अधिक हैं, जो सबूतों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देती हैं।

(4) हालाँकि एक अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरे, आरोपी को बरी कर दिए जाने के बाद उसकी बेगुनाही का अनुमान विचारण न्यायालय द्वारा फिर से पुष्ट और मजबूत हो गया है।

(5) यदि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को परेशान नहीं करना चाहिए।"

16. उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों के आधार पर, उच्च न्यायालय के फैसले की जांच करना हमारा दायित्व है कि क्या यह यहां ऊपर बताए गए मापदंडों के भीतर बारीकी से जांच करता है या एक दोषसिद्धि केवल इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि एक अलग दृष्टिकोण लिया जा सकता है। सबसे पहले, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि पक्षों के विद्वान वकील ने, बहुत कष्ट के साथ, हमें रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से अवगत कराया है। सबूतों की जांच करने पर, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता पीडब्लू-2 के पति संतोष के घर में नौकर के रूप में काम कर रही थी, जिसने सबसे पहले नोटिस किया था कि उसका बेटा आनंद, 3 1/2 साल का लड़का गायब था। आनंद के अपहरण और आरोपियों द्वारा फिरौती मांगने संबंधी पत्र भी उसे मिला था और उसने इसे अपने ससुर मनफूल को दिखाया था। जयवीर पीडब्लू-1, पुलिस स्टेशन गया था जहां उसने उस पत्र को संलग्न करते हुए एक आवेदन पूर्व पीए को प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी, दाता राम, पीडब्लू-12 संतोष के घर गए थे जहां से उन्हें दो पत्र, प्रदर्शनी पी1 और पी2 बरामद हुए थे। इन्हें घर में अलग-अलग जगहों पर रखा जाता था। मनफूल और संतोष नाम के दो व्यक्तियों की उपस्थिति में पत्र जब्त कर लिए गए। इसके बाद, वह बिजवासन गांव गए, जहां उन्हें पता चला कि विनोद कुमार उस गांव का नहीं था। जयवीर द्वारा बताया गया कि विनोद कुमार सामने आया था। बेरी के स्कूल से कुछ जांच के दौरान, जांच अधिकारी उस स्कूल में गए जहां उन्हें पता चला कि विनोद कुमार नामक व्यक्ति वहां पढ़ रहा था और पिछले सात महीनों से अनुपस्थित था। आगे की जांच में पता चला कि आरोपी ओम प्रकाश का बेटा था जिसने विनोद कुमार की तस्वीर दिखाई थी जो संतोष के पति के घर में काम करने वाले व्यक्ति की पहचान से मेल खाती थी। जब जांच इस तरह से आगे बढ़ रही थी, तो

विनोद कुमार को जीआरपी में हेड कांस्टेबल महिपाल, पीडब्लू-5 ने आनंद के साथ पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पीडब्लू-12 के साक्ष्य में यह है कि 26.9.1996 को उसने आवेदन पूर्व दायर किया था। पीएच/1 ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी विनोद की पेशी का वारंट जारी करने का आदेश दिया था और पूर्व पीएच/2 आदेश के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट होने के नाते एसीजेएम जींद ने 30.9.96 तक वारंट निष्पादित करने के निर्देश के साथ आरोपी विनाेद की पेशी का वारंट जारी करने का आदेश दिया था। . उसकी गवाही में यह भी है कि वह वारंट एक्स पीएच/3 को अधीक्षक, सेंट्रल जेल, तिहाड़, दिल्ली के पास ले गया और आरोपी विनोद कुमार की हिरासत की मांग की, लेकिन जेल अधिकारियों ने उसे सूचित किया कि वे उसे नहीं सौंपेंगे। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के औपचारिक आदेश के बिना आरोपी विनोद की हिरासत। इसके बाद उन्होंने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिन्होंने आदेश पारित किया, पूर्व। पीएच/5, उसे जेल से आरोपी विनोद की हिरासत लेने की अनुमति दी गई, जिसके बाद वह विनोद को जेल से जींद ला सका और 27.9.96 को औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार कर लिया। उच्च न्यायालय ने उचित जांच और स्पष्टता के साथ इस पहलू की सराहना की है।

17. यहां यह नोट करना उचित है कि उच्च न्यायालय ने चार पहलुओं पर ध्यान दिया है, अर्थात्, (i) आरोपी संतोष के पति जगबीर के घर में नौकर के रूप में काम कर रहा था, और खुद को उसका बेटा बताया था। बिजवासन निवासी सूरजभान और उसकी फोटो ओम प्रकाश ने दिखाई थी; (ii) कि आनंद के माता-पिता को लिखे गए पत्रों को अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित कर दिया गया है और यह दलील कि पत्र पुलिस के दबाव में लिखे गए थे, स्वीकार्य नहीं था; (iii) विद्वान परीक्षण न्यायाधीश द्वारा जिन विसंगतियों को उजागर किया गया था, वे मामूली हैं और उस संबंध में गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था; और

(iv) अन्य सह-अभियुक्त जोगिंदर के बरी होने से विनोद कुमार द्वारा निभाई गई भूमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

18. यहां यह बताना जरूरी है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दो प्रश्न उठाए हैं, अर्थात् क्या आरोपी जोगिंदर ने आरोपी विनोद कुमार को जगबीर सिंह के 31/2 वर्षीय लड़के आनंद को फिरौती के लिए अपहरण करने के लिए उकसाया था और क्या आरोपी विनोद कुमार ने आनंद को फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। और आरोपी जोगिंदर द्वारा उकसाए जाने पर एक्स पी 1 से पी 3 तक पत्र लिखा। सबूतों का विश्लेषण करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि जोगिंदर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था, वह अपीलकर्ता के खिलाफ सबूतों की जांच करने के लिए आगे बढ़े हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक पहलू यह है कि विनोद कुमार को दोषी नहीं पाया जा सकता क्योंकि जोगिंदर के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित मामले में कोई पैर नहीं है, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। अभियोजन पक्ष का मामला था कि जोगिंदर ने अपराध में सहयोग किया था क्योंकि उसने विनोद कुमार को बच्चे के अपहरण के लिए उकसाया था। हमें कोई कारण नजर नहीं आता कि उनके बरी होने से विनोद कुमार के मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के उक्त तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

19. अगला पहलू गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियों से संबंधित है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने संतोष द्वारा मनफुल को पत्र सौंपने के संबंध में विसंगतियां पाई हैं; गवाहों द्वारा बताए गए विभिन्न पहलुओं और गिरफ्तारी के समय आरोपी की पहचान से संबंधित स्थान और समय से संबंधित विसंगतियां। नोट की गई विसंगतियां बिल्कुल मामूली हैं। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि मामूली विसंगतियां इस बात पर अनावश्यक जोर दिया गया है कि किससे मुलाकात हुई, किस समय हुई और किसे रिहा

किया गया और किसके स्थान पर और किस समय रिहा किया गया आदि। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि संपूर्ण साक्ष्य मामले की जड़ को न छू पाने या मामले की जड़ तक न जाने वाले छोटे-छोटे मुद्दों पर छोटी-मोटी विसंगतियों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। यह भी एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी सच्चा गवाह संभवतः कुछ असंगत विवरण देने से बच नहीं सकता है, लेकिन न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा तभी होता है जब किसी गवाह के साक्ष्य में विसंगतियां उसके बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। के साथ इतना असंगत हो. उनके साक्ष्यों को अस्वीकार करना उचित होगा. न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन विसंगतियों को नजरअंदाज करें जो मूल संस्करणअभियोजन को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि न्यायालय को रिकॉर्ड पर संपूर्ण सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मामलों में लोगों और मामलों के अपने विशाल अनुभव का उपयोग करना होगा। [देखें उत्तर प्रदेश राज्य वी एम.के एंथोनी१३, रम्मी बनाम एम.पी. राज्य१४ और अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य१५]

20. उपरोक्त सिद्धांतों की कसौटी पर परखे जाने पर हम इससे सहमत हैं। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने वास्तव में उन विसंगतियों पर अनुचित जोर दिया है जो प्रकृति में मामूली हैं। विस्तार से बताएं तो इस बात पर जोर दिया गया है कि गिरफ्तारी मेमो में सूरजभान के बेटे विनोद कुमार का नाम दर्शाया गया है। विद्वान विचारण न्यायाधीश यह समझने में असफल रहे कि विनोद कुमार स्वयं को सूरजभान का पुत्र बता रहा है। इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि वह लड़के आनंद के साथ पाया गया था। उसकी पहचान या इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि वह संतोष के पति के घर में काम कर रहा था। यह भी साक्ष्य में लाया गया है कि हरपाल, पीडब्लू-3, ने उसे आनंद को ले जाते हुए देखा था और पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया कि वह बच्चे को लड़के के लिए जूते और अपने लिए दवा खरीदने के लिए जींद ले जा रहा था। इसके अलावा, विनोद कुमार ने

यह दलील नहीं दी है कि जगबीर ने उसे नौकरी पर नहीं रखा था। इस प्रकार, विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के अतितकनीकी दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से स्वीकार नहीं किया गया है।

21. अगला पहलू जिसकी जांच करना आवश्यक है वह यह है कि क्या आरोपी द्वारा दी गई याचिका के आधार पर प्रदर्श पी1 से पी3 तक के पत्रों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने इस पहलू पर थोड़े अनोखे ढंग से विचार किया। उनके तर्क का प्रभाव यह है कि पत्रों के अवलोकन, प्रदर्श पी 1 से पी 3, से पता चलता है कि आरोपी को 26.9.96 को सुबह-सुबह डाकघर और बस स्टैंड के पास रोहतक में फिरौती की रकम मिलनी थी। और इसलिए यदि इन पत्रों में कोई सच्चाई होती तो पुलिस को पत्रों में उल्लिखित समय तक इंतजार करना चाहिए था और पत्रों में उल्लिखित स्थान पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की व्यवस्था करनी चाहिए थी; उन परिस्थितियों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तुरंत कार्यवाही करें, खासकर उन परिस्थितियों में जब शिकायतकर्ता या पुलिस के पास आरोपी का सही पता नहीं था। जांच एजेंसी द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोई कदम नहीं उठाने की कार्यवाही को अपवाद माना गया है। पत्रों में दिए गए स्थान और उस आधारशिला पर आरोप लगाते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पत्र 24.9.96 को अस्तित्व में नहीं थे। इसके अलावा, उनके दिमाग में यह विचार आया कि तीन पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी उसी समय और, इसलिए, पत्रों पर निर्भरता एक बाद का विचार था। उन्होंने यह भी माना है कि इस प्रकार के पत्रों को अस्तित्व में लाना पुलिस के लिए असंभव नहीं है और इसलिए, अभियुक्त ने यह रुख अपनाया था कि उक्त पत्र प्राप्त किए गए थे पुलिस के दबाव में उससे लिखे गए पत्रों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता।

22. उपरोक्त तर्क को समझने के लिए सबसे पहले अभियुक्त की दलील को समझना आवश्यक है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि ये पत्र पुलिस के दबाव में लिखे गए थे. जब उन्हें पहली बार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीडब्लू-11 के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे। उक्त गवाह के साक्ष्य में यह आया है कि उसने आरोपी को पत्र दिखाए थे जिसने उसके सामने स्वीकार किया है कि पत्र उसके द्वारा लिखे गए थे। पत्रों को पढ़ा गया और उन्हें समझाया गया और उन्होंने सही होने को स्वीकार किया। अभियुक्त ने एसीजेएम के समक्ष यह नहीं कहा था कि पुलिस ने दबाव में उससे पत्र लिखवाया था। इसे ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान की सराहना की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 और उसका उत्तर निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

> "प्रश्न संख्या 2 कि लक्कस से जिंद के लिए निकलते समय आपने जाबिर के घर पर प्रदर्श P1 से प्रदर्श P3 तक पत्र छोड़े थे। आपने उन पत्रों में जगबीर और मनफूल को लिखा था कि आपने फिरौती के लिए आनंद का अपहरण कर लिया है। यदि वे आनंद को छुड़ाना चाहते थे उन्हें 26.9.96 को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच बस स्टैंड, रोहतक के पास डाकघर के पास स्थित एक स्थान पर एक लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया।
>
> उत्तर: यह ग़लत है।"

प्रश्न संख्या 9 और उस संबंध में दिया गया उत्तर इस प्रकार है:

> "प्रश्न संख्या 9 कि 28.3.96 को पुलिस स्टेशन सदर, जींद में पीडब्लू-12 द्वारा गवाहों की उपस्थिति में आपसे पूछताछ की गई थी और आपने खुलासा बयान दिया था कि मामले में आपके सह-अभियुक्त

जोगिंदर की संलिसता थी। आपने पुलिस को सूचित किया कि आरोपी जोगिंदर ने आपको आनंद का अपहरण करने के लिए उकसाया था और आपसे पूर्व. और आपके प्रकटीकरण विवरण प्रदर्श पी सी पर हस्ताक्षर किए।

उत्तर. यह ग़लत है. मैंने कभी भी प्रकटीकरण विवरण प्रदर्श पी सी नहीं दिया और प्रदर्श पी1 और पी2 की सामग्री को कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे हस्ताक्षर जबरन लिए गए और पुलिस के दबाव में मुझसे ये पत्र लिखवाए गए."

23. हमने बयान को विस्तार से संदर्भित किया है क्योंकि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में कहा है कि जब सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच की गई तो आरोपी ने एक शब्द भी नहीं बताया कि जोगिंदर ने उससे पत्र लिखवाए थे या पत्र लिखवाए गए थे। पुलिस द्वारा दबाव में. ऐसा अवलोकन प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के अनुरूप है। दूसरा उत्तर थोड़ा विचलन करता है, क्योंकि जो प्रश्न उनसे पूछा गया था वह प्रकटीकरण विवरण के संबंध में था और पत्र जोगिंदर के कहने पर लिखे गए हैं। जो भी हो, यह मानते हुए भी कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान में यह दलील दी गई थी कि उसने पुलिस के दबाव में आकर पत्र लिखा था, उक्त रुख दो आधारों पर स्वीकार करने योग्य नहीं है, अर्थात्, i) वह जब अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीडब्लू-11 द्वारा उन्हें पत्र दिखाए गए थे, तब उन्होंने यह आरोप नहीं लगाया था और वास्तव में उन्होंने पत्रों की सत्यता को स्वीकार किया था और ii) गवाहों की जिरह में एक बेतुके सवाल को छोड़कर पीडब्लू-12, पत्रों के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है। यहां यह कहना उचित है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू-11 के रूप में पूछताछ की गई है और उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि पत्र उनके सामने पेश किए गए थे और

आरोपी-अपीलकर्ता ने पत्रों की पहचान की थी और अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए थे। जिरह में कुछ भी पता नहीं चला है। इसी तरह, किसी भी गवाह से वास्तव में कोई जिरह नहीं की गई है कि पत्र पुलिस के दबाव में लिखे गए थे।

24. इस संदर्भ में, हम यूपी राज्य बनाम नाहर सिंह 16 में प्राधिकरण का संदर्भ उपयोगी रूप से ले सकते हैं, जिसमें न्यायालय ने जिरह की अनुपस्थिति के प्रभाव से निपटा है। यह सच है, उसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स अलग था, लेकिन टिप्पणियाँ प्रमुख हैं। उक्त मामले में, यह आयोजित किया गया है:

> "13..... देरी के स्पष्टीकरण पर जिरह के अभाव में, पीडब्लू 1 के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई और उच्च न्यायालय को उस पर विश्वास करना चाहिए था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 विपरीत पक्ष द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत गवाह से जिरह करने का मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है। उस प्रावधान का दायरा साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 द्वारा एक गवाह से पूछताछ की अनुमति देकर बढ़ा दिया गया है:
>
> (1) उसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए,
>
> (2) यह पता लगाना कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, या
>
> (3) उसके चरित्र को चोट पहुँचाकर उसकी साख को हिला देना, हालाँकि ऐसे सवालों के जवाब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे दोषी ठहरा सकते हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे दंड या ज़ब्ती के लिए उजागर कर सकते हैं।

14. लॉर्ड हर्शेल, एल.सी. का अक्सर उद्धृत अवलोकन ब्राउन बनाम डन१७ में उन प्रावधानों के अंतर्निहित सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है। यह इस प्रकार पढ़ता है:

"मैं यह कहने से खुद को नहीं रोक सकता, कि मुझे लगता है कि यह किसी मुद्दे के उचित आचरण के लिए बिल्कुल आवश्यक है, जहां इसका उद्देश्य सुझाव देना है

यह कि एक गवाह किसी विशेष बिंदु पर सच नहीं बोल रहा है, जिरह में पूछे गए कुछ सवालों से उसका ध्यान तथ्य की ओर आकर्षित करने के लिए यह दिखाया जाता है कि आरोप लगाने का इरादा है, और उसके साक्ष्य को नहीं लेना और इसे पूरी तरह से चुनौती रहित मामले के रूप में पारित करना और फिर, जब उसके लिए यह समझाना असंभव है, जैसा कि शायद वह ऐसा करने में सक्षम हो सकता था यदि उससे ऐसे प्रश्न पूछे गए होते, तो सुझाव दिया गया है कि परिस्थितियाँ संकेत करती हैं कि वह जो कहानी सुनाता है उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तर्क दें कि वह श्रेय के अयोग्य गवाह है। माय लॉर्ड्स, मैंने हमेशा यह समझा है कि यदि आप किसी गवाह पर महाभियोग चलाने का इरादा रखते हैं, तो जब तक वह कठघरे में है, आप कोई भी स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के लिए बाध्य हैं, जो उसके लिए खुला है और, जैसा कि मुझे लगता है, वह है। किसी मामले के संचालन में न केवल पेशेवर अभ्यास का नियम है, बल्कि गवाहों के साथ निष्पक्ष व्यवहार और निष्पक्ष व्यवहार भी आवश्यक है।"

जैसा कि उक्त मामले में कहा गया है, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को मंजूरी नहीं दी कि देरी के लिए स्पष्टीकरण बिल्कुल भी ठोस नहीं था और उक्त विचार व्यक्त किया गया था क्योंकि कोई जिरह नहीं हुई थी। वर्तमान मामले में, गवाह की जिरह के अभाव में, पीडब्लू-12 को एक स्पष्ट सुझाव को छोड़कर, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि अपीलकर्ता पत्रों का लेखक था और ये किसी दबाव में नहीं लिखे गए थे।

25. हमने ऊपर जो कहा है उसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि अपहृत लड़का रेलवे स्टेशन पर बरामद किया गया था। आरोपी ने यह नहीं बताया कि बच्चे को दिल्ली कैसे लाया जा सकता है। हरपाल ने स्पष्ट रूप से बताया कि उसने आनंद को विनोद कुमार के साथ देखा था। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने हरपाल के साक्ष्य में कुछ विसंगतियों को नोट किया है, लेकिन बिना किसी उचित कारण के। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने वास्तव में महत्वहीन और अनावश्यक विवरणों पर ध्यान दिया है। हरपाल की ओर से विनोद कुमार से सवाल पूछना काफी स्वाभाविक है क्योंकि वह एक घरेलू नौकर को बच्चे को ले जाते हुए देखकर थोड़ा चिंतित थे। यह मानव स्वभाव में अंतर्निहित है और इसलिए, हरपाल के संस्करण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हमारे विचार से ये पहलू अभियुक्तों पर काफी भारी पड़ते हैं।

26. उपरोक्त कोणों से परीक्षण करने पर हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पलटने का निर्णय बिल्कुल बचाव योग्य है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, योग्यता से रहित होने के कारण अपील खारिज कर दी जाती है।

निधि जैन

अपील खारिज की गई।

१. (1971)3 एस सी सी 577

२. ए आई आर 1934 पी सी 227

३. ए आई आर 1945 पी सी 151

४.ए आई आर 1952 एस सी 52

५॰ ए आई आर 1961 एस सी 715

६.(1972)1 एस सी सी 107

७.(1973)2 एस सी सी 793

८.(2005)9 एस सी सी 291

९(2004)13 एस सी सी 257

१०(2007)7 एस सी सी 625

११(2011)2 एस सी सी 83

१२(2007)4 एस सी सी 415

१३(1985)1 एस सी सी 505

१४(1999)8 एस सी सी 649

१५(1988) पूरक एस सी सी 241

१६(1998)3 एस सी सी 561

१७(1893)6 आर 67

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।